

पहले मुख्य समाचार।

- देश के सात सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क को फोर लेन करने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के दस रेलवे स्टेशन भी इस परियोजना में शामिल।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा— पिछले साढ़े नौ साल में 70 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप।
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास।
- यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में हुआ बदलाव।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा यातायात वाले सात रेलवे नेटवर्क को फोर-लेन का बनाने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके तहत दिल्ली से हावड़ा रूट उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को कवर करेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली से गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, जबकि दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर आगरा और झांसी रेलवे स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन सात कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग चालीस प्रतिशत ट्रैफिक होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के सात हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं। सब कॉरिडोर्स को फोर लाइनिंग क्वाड्रपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल।

वाराणसी में कल नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में सत्तर हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है।

हमने पिछले नौ साढ़े नौ वर्षों में 70 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी दी है इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा हो आंगनबाड़ी केंद्र उसके टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इसके निर्माण में। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेय जल की ये इसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज यहां पर बाल वाटिकाएं चलती हैं, खेल-खेल में कैसे अक्सर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह की इस वर्ष की थीम— मेरी आंगनबाड़ी—मेरी जिम्मेदारी को जनभागीदारी से जोड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का बचपन स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित होगा।

आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं गांव और गलियों से होकर के या आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और यह सब शुरूआत हुई है। एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और उसकी थीम इसी लिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है।

सुपोषित बचपन स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहे और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में आयोजित कामकाजी महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रही है।

हमने बेटियों और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत शीघ्र स्नातक फाइनल ईयर की बालिकाओं को, 50 हजार मेधावी बेटियों को, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पीलीभीत में पन्द्रह करोड़ रुपये की लागत से खोले गए वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया। मेरठ के बाद यह देश का दूसरा बासमती और जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का लाभ सिर्फ पीलीभीत ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के किसान भी उठाएंगे।

जनपद के किसान, हमारे नौजवान, हमारे उद्योग जगत के लोग इस केंद्र का फायदा उठाएंगे और जो इस सरकार का डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का प्रण है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी, किसानों की आय बढ़ानी और इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का और हम लोग कैसे फायदा बढ़ा सकें वो ये केंद्र साकार करके देगा।

इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस केंद्र का लाभ प्रदेश के उन तीस जिलों के किसानों को भी मिलेगा, जिन्हें बासमती उत्पादन में जीआई टैग मिला है।

लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वह जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति-दिशा की बैठक में भी शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाईस्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है।

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान, गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा, जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था, जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। समाचार कक्ष से अरुण।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष से बढ़ाकर सत्तर वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है, जिससे मरीजों को वरिष्ठ और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुभव का फायदा मिल सके।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की उम्र है वो चिकित्सकीय कार्य के लिए 70 वर्ष तक कर दी गई है। यानी अपने 70 में वर्ष तक उम्र के वो सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सकीय कार्य कर सकेंगे। जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सक है उन्होंने इतना लंबा अनुभव हमारे अस्पतालों में प्राप्त किया है। और ये निर्णय जनहित में लिया गया कि मरीजों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी तीन दिनों तक बारिश का यह क्रम जारी रहेगा। उधर, बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के छब्बीस जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी जगहों पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
